क्रांति समय
हिन्दी दैनिक अखबार में विज्ञापन, प्रैस नोट, जन्म दिन की शुभकामनाएँ, या अपने विस्तार में किसी भी समस्या को अखबार में प्रकाशित करने के लिए संपर्क करें:-
बी-4 घंटी वाला कॉम्पलेक्ष उधना तीन रास्ता, उडुप्पी होटल के बगल में, सूरत-394210
मो. 9879141480

दैनिक
क्रांति समय

RNI.No. : GUJHIN/2018/75100

क्रांति समय
हमारे यहां पर एल.आई.सी., कार-बाईक-ट्रक का इन्सयोरेंशन, रेल टिकट, एयर टिकट बनवाने के लिए संपर्क करें:-
बी-4 घंटी वाला कॉम्पलेक्ष उधना तीन रास्ता, उडुप्पी होटल के बगल में, सूरत-394210
मो. 8980974047

संपादक : सुरेश मौर्या मो. 9879141480
E-mail: krantisamay@gmail.com
सूरत, वर्ष: 02 अंक: 52, शनिवार, 16 मार्च, 2019, पेज: 4, मुल्य 1 रु.
रजीस्ट्रड ऑफिस:- 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात
Email: krantisamay@gmail.com Web site : www.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

पहला कॉलम

तृणमूल कांग्रेस का 48 घंटे का धरना शुरू, भाजपा ने बताया ड्रामा

कोलकाता । सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में सभी मतदान केंद्रों को अति संवेदनशील घोषित करने की अपील कर राज्य की छवि धूमिल करने की भाजपा की कथित कोशिश के खिलाफ 48 घंटे का अपना धरना शुक्रवार को शुरू किया। तृणमूल की महिला कार्यकर्ता यहां एस्प्लानेड में धरने पर बैठीं। हालांकि, भाजपा ने इस धरने को ड्रामा करार दिया है। तृणमूल कांग्रेस की महिला शाखा की प्रमुख चंद्रिमा भट्टाचार्य ने दावा किया कि भाजपा का पश्चिम बंगाल में आधार नहीं है, उसके बाद भी वह केंद्रीय बलों का इस्तेमाल कर चुनाव जीतने की उम्मीद कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा और उसके नेता सपनों की दुनिया में खोए हुए हैं। उन्होंने कहा, 'बंगाल में कानून व्यवस्था अच्छी है। उसके बाद भी भाजपा मांग कर रही है कि राज्य को अतिसंवेदनील घोषित किया जाए।' भट्टाचार्य ने सवाल किया कि क्या यह पश्चिम बंगाल के लोगों का अपमान नहीं है। उन्होंने कहा, 'हम अपने राज्य की छवि धूमिल करने की किसी भी कोशिश का विरोध करेंगे।' भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हाथों में तख्तियां ले हुईं महिला तृणमूल कार्यकर्ताओं ने केंद्र के विरूद्ध नारेबाजी की। तृणमूल के धरने पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि पार्टी (तृणमूल कांग्रेस) को तय करना है कि वह चुनाव लडना चाहती है या फिर धरना जारी रखना चाहती है। उन्होंने कहा, 'तृणमूल कांग्रेस को यह ड्रामा बंद करना चाहिए।' भाजपा ने चुनाव आयोग से पश्चिम बंगाल में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए उसे अति संवेदनशील राज्य घोषित करने की मांग की थी। उसकी यह भी मांग की थी कि राज्य के हर मतदान केंद्र पर केंद्रीय बल तैनात किए जाएं । पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को आरोप लगाया था कि भाजपा केंद्रीय बलों की आड़ में छिपाने का प्रयास कर रही है क्योंकि वह राज्य में एक भी सीट नहीं जीत सकती है।

नीतीश कुमार को राहत, 28 साल पुराने हत्या के मामले में पटना कोर्ट ने किया निरस्त

पटना । बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ निचली अदालत द्वारा 28 साल पुराने एक हत्या के मामले में लिए गए संज्ञान को पटना उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को निरस्त कर दिया। पटना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति ए. अमानुल्लाह की एकल पीठ ने पटना जिले के पंडारक में 16 नवंबर, 1991 को हुई हत्या के मामले में नीतीश कुमार द्वारा दर्ज याचिका की सुनवाई के बाद निचली अदालत के फैसले को निरस्त कर दिया। अदालत ने इस मामले में 31 जनवरी को दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी कर ली थी और फैसला सुरक्षित रख लिया था। उल्लेखनीय है कि पंडारक के ढीबर गांव में 16 नवंबर, 1991 को बाढ़ संसदीय क्षेत्र के मध्यावधि चुनाव के लिए हुए मतदान के दिन ग्रामीण सीताराम सिंह की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में दर्ज प्राथमिकी में नीतीश कुमार सहित कुल पांच लोगों को आरोपी बनाया गया था। लेकिन बाद में नीतीश कुमार सहित दो लोगों को पुलिस ने जांच के बाद आरोपमुक्त कर दिया था।

आतंकी मसूद की संपत्ति जब्त करेगा फ्रांस, पाक ने फिर किया कार्रवाई करने से इनकार

नेशनल डेस्क। आतंकी गुट जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को पाकिस्तान गिरफ्तार नहीं करेगा। पाकिस्तान ने कहा कि भारत द्वारा मसूद पर सौंपे गए सबूत कांफी नहीं है। पाकिस्तान ने अपना दोहरा चेहरा दिखाते हुए कहा कि भारत ने जो सबूत सौंपे हैं उससे यह जाहिर नहीं होता कि आतंकी हमलों में मसूद का कोई हाथ है। वहीं, फ्रांस ने आतंकी संगठन पर खुद ही ऐक्शन लेने का फैसला किया कि जैश सरगना मसूद की देश में जितनी भी संपत्तियां हैं उसे जब्त करेगा। जैश पर फ्रांस की यह अब तक की सबसे पड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित किए जाने के मार्ग को चीन के चौथी बार बाधित करने से नाराज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने चेतावनी दी है कि यदि चीन अपनी इस नीति पर अड़ा रहा तो जिम्मेदार सदस्य परिषद में ''अन्य कदम उठाने पर मजबूर'' हो सकते हैं। सुरक्षा परिषद के एक दूत ने चीन को असामान्य कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि यदि चीन इस कार्य में बाधा पैदा करना जारी रखता है तो जिम्मेदार सदस्य देश सुरक्षा परिषद में अन्य कदम उठाने पर मजबूर हो सकते हैं। ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। यहां बता दें कि फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ''1267 अल कायदा सैंक्शन्स कमेटी'' के तहत अजहर को आतंकवादी घोषित करने का प्रस्ताव 27 फरवरी को पेश किया था। 13 मार्च को इस पर सुनवाई होनी थी लेकिन चीन ने समय सीमा खत्म होने से पहले ही वीटो डाल कर मसूद को फिर से बचा लिया। गौरतलब है कि 14 फरवरी को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में जैश-ए-मोहम्मद के आत्मघाती हमलावर ने सीआरपीएफ के काफिले पर हमला किया था, जिसमें 40 जवान शहीद हो गए थे। इस हमले के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। चीन द्वारा रोड़ा अटकाने को लेकर अमेरिका के एक सांसद ने निराशा जाहिर करते हुए कहा कि चीन के पास अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने का बेहतर अवसर था। हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के अध्यक्ष, सांसद इलियट इंगेल ने बृहस्पतिवार को कहा कि मैं निराश हूं कि चीन ने फिर से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित किए जाने के मार्ग में रोड़ा अटकाने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि जैश-ए-मोहम्मद पुलवामा के अलावा भारत के विभिन्न हिस्सों में दो दशक में हुए कई आतंकी हमलों में शामिल रहा है जिनमें 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद पर हुआ हमला भी शामिल है।

लोकसभा चुनावः

राहुल गांधी अमेठी के साथ दक्षिण भारत से भी लड़ सकते हैं चुनाव

नई दिल्ली ।

लोकसभा चुनाव जीतने को लेकर सभी दलों ने पूरा जोर लगा रखा है। ज्यादा से ज्यादा लोगों का भरोसा जीतने के लिए आए दिन नई रणनीति का खुलासा हो रहा है। इसी कड़ी में चर्चा तेज है कि कांग्रेस ने पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी को इस बार उनकी पारंपरिक सीट अमेठी के अलावा, दक्षिण भारत की किसी सीट से चुनाव लड़ाने का पूरा मन बना लिया है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस की योजना यह है कि यदि राहुल गांधी किसी अनय सीट से चुनाव लड़ते हैं तो उसके आसपास की सीटों पर भी माहौल बनेगा और कांग्रेस को बढ़त मिल सकती है। खासतौर पर दक्षिण भारत में यदि राहुल अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं तो हिंदी पट्टी में कमजोर दिख रही कांग्रेस एक तरह से भरपाई की स्थिति में आ सकती है। बता दें कि बीते लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी और वड़ोदरा की दो लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ा था। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी राहुल से मांग की है कि उन्हें अमेठी के अलावा दक्षिण भारत की किसी सीट से भी चुनाव लड़ना चाहिए। इससे पहले उनके महाराष्ट्र के नांदेड़ से चुनाव लड़ने की चर्चाएं चल रही थीं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण की इस सीट पर राहुल के उतरने के कयास को उस वक्त और बल मिला जब पूर्व सीएम ने बयान दिया कि अगर राहुल यहां से लड़ना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। उन्होंने कहा था, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं। वह किसी भी लोकसभा सीट से सफलतापूर्वक लड़ सकते हैं। बता दें कि राहुल गांधी ने मार्च 2004 में राजनीति में एंट्री का ऐलान किया था। वह लगातार तीन बार से उत्तर प्रदेश के अमेठी लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। वह पहली बार इस सीट से मई 2004 में निर्वाचित हुए थे।

आज आ सकती है भाजपा की पहली लिस्ट,मोदी की सीट का भी होगा ऐलान

नई दिल्ली।

भारतीय जनता पार्टी आगामी लोकसभा चुनावों के लिए शनिवार को उम्मीदवारों के नाम की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। इस लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा, राधामोहन सिंह की टिकटों का ऐलान भी हो सकता है कि वे कहां से चुनाव लड़ेंगे। शनिवार को दिल्ली भाजपा मुख्यालय में पार्टी चुनाव समिति की पहली बैठक होने जा रही है और ऐसी अटकले हैं कि कल लगभग 100 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान बैठक में पीएम मोदी भी मौजूद रहेंगे। उल्लेखनीय है कि पिछले काफी समय से चर्चाओं का बाजार गर्म है।

कि पीएम मोदी इस बार ओडिशा की पुरी लोकसभा सीट से भी चुनाव लड़ सकते हैं। मोदी अभी वाराणसी से सांसद हैं। बता दें कि लोकसभा चुनावों को देखते हुए अलग-अलग दलों ने अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करनी शुरू कर दी है।

कांग्रेस, सपा ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है लेकिन अभी भाजपा ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं।

यूपी में असमंजस खत्मः अपना दल और भाजपा साथ लड़ेंगे लोकसभा चुनाव

लखनऊ ।

उत्तर प्रदेश में भाजपा और अपना दल के बीच लंबे वक्त से चली आ रही राजनीतिक खींचतान खत्म हो गई है। दोनों दलों ने एक बार फिर लोकसभा चुनाव एक साथ लड़ने की घोषणा कर दी है। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने शुक्रवार को औपचारिक रूप से यह ऐलान कर दिया है कि बीजेपी और अपना दल यूपी में गठबंधन करेगी और अनुप्रिया की पार्टी को पिछले समझौते की तरह इस बार भी दो सीटें दी जाएंगी। दोनों दलों के बीच यह सहमति दिल्ली में अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की बैठक के बाद बनी है। अमित शाह ने यह भी ऐलान किया है कि इस गठबंधन की ओर से केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल मीरजापुर की लोकसभा सीट पर दावेदारी करेंगी। शाह ने यह स्पष्ट किया है कि अभी गठबंधन की दूसरी सीट पर फैसला नहीं हुआ है। बता दें कि साल 2014 में भी अपना दल और बीजेपी के बीच यूपी में समझौता हुआ था। 2014 के चुनाव में अनुप्रिया पटेल की पार्टी को प्रदेश की दो लोकसभा सीटों पर जीत मिली थी। इनमें मीरजापुर की सीट से अनुप्रिया पटेल और प्रतापगढ़ लोकसभा सीट से पार्टी नेता कुंवर हरिवंश सिंह चुनाव जीते थे। चुनाव जीतने के बाद अनुप्रिया पटेल को केंद्र में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का राज्यमंत्री भी बनाया गया था, लेकिन 2017 में यूपी में हुए लोकसभा चुनाव के बाद से ही अनुप्रिया और बीजेपी के बीच रिश्ते तल्ख हो गए थे। अनुप्रिया के पति और एमएलसी आशीष पटेल ने जहां बीजेपी पर अपना दल की अनदेखी करने का आरोप लगाया था, ।

वहीं प्रदेश की सरकार की खिलाफत करते हुए अनुप्रिया ने भी यह कहा था कि उन्हें किसी सरकारी कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया जा रहा है। अनुप्रिया ने इससे नाराज होकर तमाम सरकारी कायक्रमों का बहिष्कार भी किया था। पूर्व में यह माना जा रहा था कि अनुप्रिया बीजेपी का दामन छोड़कर गठबंधन के साथ जा सकती हैं, लेकिन समय बीतते बीजेपी ने अपने सहयोगी को मना लिया।

लोकसभा चुनाव के लिए किसी भी राज्य में गठबंधन में दिक्कत नहीं: कांग्रेस

नई दिल्ली। कांग्रेस ने शुक्रवार को कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी को किसी भी राज्य में गठबंधन करने में कोई दिक्कत नहीं है और मामूली मतभेदों को दूर कर लिया जाएगा। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि मूल मकसद लोगों के पक्ष में शासन व्यवस्था को चलाना है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उल्लेख करते हुए कहा कि कांग्रेस का अन्य दलों के साथ गठबंधन किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं बल्कि भारत के लोगों के लिए हैं। उन्होंने कहा कि बिहार समेत किसी भी राज्य में कांग्रेस को चुनावी गठबंधन करने में कोई दिक्कत नहीं है। इसके बावजूद अगर कोई मतभेद या परेशानी है तो उसे दूर कर लिया जाएगा। पार्टी महासचिव प्रियंका वाड्रा की भीम सेना के प्रमुख चंद्र शेखर आजाद की मुलाकात के संबंध में उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा से स्वतंत्र आवाज के पक्ष में हैं और जहां कहीं भी लोगों की आवाज को दबाया जाएगा तो पार्टी वहां रहेगी। कांग्रेस के कई नेताओं के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने पर कहा कि मोदी 'कांग्रेस मुक्त भारत' बनाने चले थे ।

पश्चिम बंगाल में ममता बैनर्जी को हराने के लिए भाजपा को मिली संजीवनी

कोलकाता ।

पश्चिम बंगाल में पैठ मजबूत करने के प्रयास में जुटी भारतीय जनता पार्टी को भाटपारा से तृणमूल कांग्रेस) के विधायक अर्जुन सिंह के पार्टी में शामिल होने से आम चुनाव से पहले राज्य में नयी संजीवनी मिली है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में मजबूत पकड़ रखने वाले और 18 वर्ष से विधायक श्री सिंह के अपने गढ़ बैरकपुर संसदीय सीट से भाजपा के टिकट पर आम चुनाव में उतरने की उम्मीद है । श्री सिंह के भाजपा का दामन थामने को तृणमूल के लिए राजनीतिक गलियारों में आम चुनाव से पहले बड़े झटके रुप में देखा जा रहा है । वर्ष 2001 से विधायक श्री सिंह की पार्टी में हिंदी भाषी नेता के रुप में पहचान थी । उनकी बैरकपुर क्षेत्र में खासी पकड़ बताई जाती है। श्री सिंह का नाम आम चुनाव में बैरकपुर से तृणमूल उम्मीदवार के रुप में सबसे आगे चल रहा था किंतु पार्टी प्रमुख मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिनेश त्रिवेदी पर भरोसा जताया। भाजपा में शामिल होने के बाद सिंह ने कहा मैं वास्तव में अर्जुन की भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं और मुकुल दा (तृणमूल के पूर्व सांसद) मेरे सारथी के रुप में साथ रहेंगे। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से काफी सीटें जीतने के लक्ष्य के लिए पार्टी चोगा और खंजर नीति के तहत तृणमूल के बड़े नेताओं को अपनी तरफ खींचने में जुटी हुई है। सिंह के भाजपा का दामन थामने से पहले तृणमूल के दो सांसदों बिशनपुर से सौमित्र खान और बोलपुर से अनुपम हजारा भी सुश्री बनर्जी से अलग होकर भाजपा की सेवा में जुट गए हैं।

कांग्रेस के बागदा से विधायक दुलाल चंद्र बार और हबीबपुर से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक खागेन मुर्मु ने भी आम चुनाव से पहले भाजपा का दामन थाम लिया है । इन पांच नेताओं के अलावा अल्पसंख्यक समुदाय के कई नेता भाजपा में शामिल हो चुके हैं। सोलहवीं लोकसभा में भाजपा के पश्चिम बंगाल से दो सांसद एस एस अहलूवालिया(दार्जिलिंग) और बाबुल सुप्रियो(आसनसोल) हैं । दोनों मोदी सरकार में मंत्री हैं। भाजपा और दलों के बड़े चेहरों को साथ में लाकर सुश्री बनर्जी की पकड़ को ढीली करने के प्रयास में राज्य से अपने सांसदों की संख्या बढ़ाने में जुटी हुई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आसनसोल और दार्जिलिंग की सीटों पर मौजूद सांसदों का फिर से चुना जाना मुश्किल नजर आ रहा है। भाजपा ने आम चुनाव में अपनी कुल सीटों की संख्या में इजाफा करने के लिए पश्चिम बंगाल को प्राथमिकता वाले राज्यों की सूची में रखा है। शाह का राज्य की 42 सीटों में से 22 सीटें जीतने का लक्ष्य है । हालांकि भाजपा नेताओं का दावा है कि उनके सांसदों की संख्या दो से बढ़कर 10 तक पहुंच सकती है। भाजपा सूत्रों के अनुसार पुरुलिया, बांकुरा, वर्धमान पूर्व, मेदिनीपुर , झारगाम , बारासत , हावड़ा , हुगली के साथ साथ कोलकता उत्तर जैसी शहरी सीटों पर भी नजर है।

बांग्लादेश क्रिकेट टीम बाल-बाल बची

न्यू जीलैंड की दो मस्जिद में गोलीबारी, ४९ की मौत

पहला हमला अल नूर मस्जिद में हुआ था जबकि दूसरा हमला क्राइस्टचर्च के उपनगरीय इलाके लिनवुड में हुआ था : चार लोगों को गिरफ्तार किया

वेलिंग्टन। न्यू जीलैंड के क्राइस्टचर्च की दो मस्जिदों में अज्ञात हमलावरों की गोलीबारी में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर ४९ हो गया है। अस्पताल में भर्ती २० गंभीर रूप से घायलों में ९ और लोगों की मौत हो गई है। न्यू जीलैंड की प्रधानमंत्री जैसिंडा ऑर्डर्न ने पहले बताया था कि अल नूर मस्जिद में ३० लोगों की मौत हुई है जबकि लिनवुड मस्जिद में १० लोग मारे गए हैं। लेकिन पुलिस कमिश्मर माइक बुश के अनुसार मृतकों का आंकड़ा ४९ तक पहुंच गया है। गौरतलब है कि पहला हमला अल नूर मस्जिद में हुआ था जबकि दूसरा हमला क्राइस्टचर्च के उपनगरीय इलाके लिनवुड में हुआ था। अल नूर मस्जिद में गोलीबारी के वक्तबांग्लादेश की क्रिकेट टीम मस्जिद में मौजूद थी, लेकिन वह सुरक्षित बच निकलने में कामयाब रही। ऑर्डर्न ने बताया कि चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है और विस्फोटक उपकरणों को निष्क्रिय किया गया है। न्यू जीलैंड की प्रधानमंत्री ने पूर्व नियोजित हमला बताया। उन्होंने इस हमले को न्यूज ीलैंड के सबसे काले दिनों में से एक बताया। ऑर्डर्न ने कहा कि क्राइस्टचर्च में हुआ घटनाक्रम 'हिंसा की असाधारण करतूत' को दर्शाता है। उन्होंने स्वीकार किया कि पीड़ितों में कई प्रवासी और शरणार्थी हो सकते हैं। मृतकों के अलावा २० से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्होंने कहा, यह स्पष्ट है कि इसे अब केवल आतंकवादी हमला ही करार दिया जा सकता है। हम जितना जानते हैं, ऐसा लगता है कि यह पूर्व नियोजित था। उन्होंने कहा, संदिग्ध वाहनों से जुड़े दो विस्फोटक उपकरण बरामद किए गए हैं और उन्हें निष्क्रिय कर दिया गया है। न्यू जीलैंड पुलिस ने गोलीबारी के संबंध में चार लोगों को हिरासत में लिया है जिनमें एक महिला है। पुलिस ने हिरासत में लिए गए लोगों की विस्तृत जानकारी नहीं दी, लेकिन हमले की जिम्मेदारी लेने वाले एक व्यक्तिने ७४ पृष्ठीय प्रवासी विरोधी घोषणापत्र छोड़ा है जिसमें उसने यह बताया है कि वह कौन है और उसने हमले को क्यों अंजाम दिया। उसने बताया कि वह २८ वर्षीय श्वेत ऑस्ट्रेलियाई है। आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने पुष्टि की कि गिरफ्तार किए गए चार लोगों में एक आस्ट्रेलियाई नागरिक है। मॉरिसन ने कहा कि क्राइस्टचर्च में एक दक्षिणपंथी, हिंसक आतंकवादी ने गोलीबारी की।

संपादकीय

चुनावी मोर्चे पर कांग्रेस

कांग्रेस ने अपना चुनावी बिगुल फूंक दिया है। अहमदाबाद में अपनी कार्यसमिति की बैठक में पार्टी ने अपनी चुनावी रणनीति (ष्ठ्ठद्दह्लद्धह्यह्य) के संकेत दिए और प्रियंका गांधी ने यहीं से बाकायदा अपने चुनावी अभियान और पॉलिटिकल करियर की शुरूआत की। अहमदाबाद में कार्यसमिति की बैठक आयोजित कर कांग्रेस ने यह संदेश भी देना चाहा है कि महात्मा गांधी की विरासत उसी के पास है और यही उसकी मूल पूंजी है। वह गांधीवादी मूल्यों की राजनीति करती है और गांधीवाद को ही बीजेपी के राष्ट्रवाद का जवाब मानती है। कांग्रेस ने बताना चाहा है कि बीजेपी का राष्ट्रवाद घृणा और उन्माद पर टिका है, जबकि गांधी की देशभक्ति की बुनियाद में सबको गले लगाने और सबको साथ लेकर चलने का भाव है। वायुसेना के एयर स्ट्राइक के बाद बीजेपी ने तमाम मुद्दों को दरकिनार कर राष्ट्रवाद को ही अपना अजेंडा बना रखा है और इसके नाम पर एक मजबूत सरकार के लिए वोट मांग रही है। अपनी इस रणनीति के जरिए उसने कुछ हद तक विपक्ष को बैकफुट पर धकेल दिया है। लेकिन इसकी काट के रूप में कांग्रेस सहिष्णु राष्ट्रवाद को आक्रामक राष्ट्रवाद के विकल्प की तरह प्रस्तुत करना चाहती है। प्रियंका गांधी ने अपने संबोधन में कहा कि यह देश प्रेम, सद्भावना और आपसी लगाव के आधार पर बना है। मैं दिल से कहना चाहती हूं कि इससे बड़ी कोई देशभक्ति नहीं है कि आप जागरूक बनें। आपकी जागरूकता एक हथियार है। यह ऐसा हथियार है, जिससे किसी को दुख नहीं देना, किसी को चोट नहीं पहुंचानी। पर यह आपको मजबूत बनाएगा। बहरहाल, कांग्रेस ने राष्ट्रवाद पर बीजेपी को जवाब जरूर दिया है पर इसे मुख्य चुनावी मुद्दा बनाने से वह बचना चाहती है। उसे लगता है कि जनता के दुख-दर्द को सामने लाकर ही वह न सिर्फ अपनी अलग छवि बना सकती है, बल्कि इन्हीं मुद्दों पर बीजेपी को घेर भी सकती है। इसलिए प्रियंका ने कार्यकताओं को सचेत किया कि असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की लगातार कोशिश की जाएगी, लेकिन वे रोजगार, किसानों और महिला सुरक्षा के मुद्दों को लेकर सवाल पूछते रहे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने साफ किया कि बीजेपी के अजेंडे में फंसने के बजाय बेरोजगारी, किसान, राफेल में भ्रष्टाचार और सरकार के वायदे पूरा न करने के मसले को लेकर ही जनता के पास जाया जाए। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जनता का ध्यान राष्ट्रवाद से हटाकर वह रोजमर्रा के मुद्दों पर कैसे लाए। उसने संगठन मजबूत करने पर ध्यान देना शुरू किया है और हार्दिक पटेल जैसे जमीनी नेताओं को अपना हिस्सा बनाया है। लेकिन पूरे विपक्ष को साथ लेकर चलने में वह अभी ज्यादा कामयाब होती नहीं दिख रही। कई राज्यों में गठबंधन का मामला लटका हुआ है या अस्पष्ट है। देखना है, सत्तापक्ष के सामने वह कितनी चुनौती पेश कर पाती है।

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने साफ किया कि बीजेपी के अजेंडे में फंसने के बजाय बेरोजगारी, किसान, राफेल में भ्रष्टाचार और सरकार के वायदे पूरा न करने के मसले को लेकर ही जनता के पास जाया जाए।

उन्मत्त राष्ट्रवाद और चुनाव

राजेंद्र शर्मा/ विश्लेषण

पुलवामा की घटना के दूसरे-तीसरे दिन से ही भाजपा अध्यक्ष, अमित शाह ने अपनी पार्टी की सभाओं में इसके दावे शुरू कर दिए थे कि देश में चूंकि अब पहले वालों की नहीं, मोदी की सरकार है, पुलवामा का पूरा बदला लिया जाएगा! उधर, खुद प्रधानमंत्री ने चुरू की सभा से ही, जहां से राजनीतिक सभाओं के मंच पर पृष्ठभूमि में शहीद जवानों की तस्वीरें लगाए जाने का चलन शुरू हुआ, बदले की भाषा का सिलसिला चालू कर दिया था।

पुलवामा की घटना से लेकर, चुनाव की तारीखों की घोषणा के बीच गुजरे तीन सप्ताह से कुछ ज्यादा के दौरान सत्ताधारी भाजपा ने जो कुछ कहा और किया है, उसके बाद इसमें किसी संदेह की गुंजाइश नहीं रह जाती है कि उसके हिसाब से उसके हाथ बाजी पलटने वाला मुद्दा लग गया है। इसे तलवार और ढाल दोनों ही बनाकर, वह न सिर्फ मोदी राज की पांच साल की चौतरफा विफलताओं के लिए विपक्ष के हमलों से, अपना बचाव कर सकती है बल्कि अपने विरोधियों को बचाव पर भी डाल सकती है। इसकी शुरुआत तो सीआरपीएफ जवानों की शहादत और अंत्येष्टियों का, सत्ताधारी भाजपा व संघ परिवार और उसके वफादार मीडिया द्वारा आतंकवाद और पाकिस्तान के विरोध के नाम पर, उन्माद जगाने के लिए इस्तेमाल किए जाने से ही हो चुकी थी। और पुलवामा के आतंकी हमले के जवाब के तौर पर, सीमा पार पाकिस्तान के खैबर-पख्तूनख्वा प्रांत में बालाकोट के जैश-ए-मोहम्मद का शिविर माने जाने वाले परिसर पर हवाई हमले किए जाने के बाद तो उन्मत्त राष्ट्रवादी दुहाई के सहारे चुनाव की वैतरणी पार करने की सत्ताधारी पार्टी की कोशिश, अपने पूरे कद में सामने आ गई। बेशक, यह कोई संयोग ही नहीं था कि पुलवामा पर हमले के बाद गुजरे तीन हफ्तों में नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार और पार्टी के अन्य शीर्ष नेताओं ने, अपने चुनाव-केंद्रित सरकारी-गैरसरकारी कार्यक्रमों का सिलसिला ज्यों का त्यों जारी रखा था, जबकि उनके विरोधी कई दिनों तक राजनीतिक आयोजनों से बचते रहे थे। सभी ने देखा है कि किस तरह इन कार्यक्रमों का, गाल-बजाऊ और छाती ठोकू आतंकवाद/ पाकिस्तान विरोध के प्रदर्शनों के जरिए, खासतौर पर मोदी की ''हिम्मतवर और फैसलाकुन' प्रधानमंत्री की छवि बनाने के लिए खुलकर इस्तेमाल किया जा रहा था। पाकिस्तान की ओर से जवाबी कार्रवाई और नष्ट हुए भारतीय मिग विमान के पायलट, अभिनंदन की वापसी के बाद तो, प्रधानमंत्री और भाजपा ने, बालाकोट कार्रवाई और अभिनंदन के नाम को, सभाओं से लेकर पोस्टरों आदि तक में और सीधे-सीधे अपने कारनामे के तौर पर जोर-शोर से भुनाना शुरू कर दिया था। पुलवामा की घटना के दूसरे-तीसरे दिन से ही भाजपा अध्यक्ष, अमित शाह ने अपनी पार्टी की सभाओं में इसके दावे शुरू कर दिए थे कि देश में चूंकि अब पहले वालों की नहीं, मोदी की सरकार है, पुलवामा का पूरा बदला लिया जाएगा! उधर, खुद प्रधानमंत्री ने चुरू की सभा से ही, जहां से राजनीतिक सभाओं के मंच पर पृष्ठभूमि में शहीद जवानों की तस्वीरें लगाए जाने का चलन शुरू हुआ, बदले की भाषा का सिलसिला चालू कर दिया था। इस सिलसिले को बालाकोट की कार्रवाई और अभिनंदन की वापसी के बाद, अपने गृह प्रदेश में अहमदाबाद के अपने संबोधन में उन्होंने ''घर में घुसकर मारने', ''सात पताल से निकालकर' मारने आदि के सिद्धांत में अपने यकीन और ''ज्यादा इंतजार नहीं करने' अपने मिजाज का बखान करने तक पहुंचा दिया। यह पूरे मामले को, एक ''निजी बदले' की मुद्राओं में ही बदल देना था। और गाजियाबाद की सभा में प्रधानमंत्री ने ''मोदी मार गया', ''मोदी मारकर चला गया' के जुमलों से, इसे शुद्ध रूप से ''निजी वीरता' के दावों तक पहुंचा दिया! अचरज नहीं कि इसी प्रक्रिया के हिस्से के तौर पर, पुलवामा की घटना के बाद के दौर में ही ''नामुमकिन अब मुमकिन है' के मोदी राज के सरकारी विज्ञापन अभियान के नारे को, भाजपा के ''मोदी है तो मुमकिन है' के नारे तक पहुंचा दिया गया। मोदी राज के लिए उग्र-राष्ट्रवादी छवि गढ़ने के इसी अभियान के दूसरे पहलू के तौर पर, विपक्ष को अगर राष्ट्रविरोधी नहीं तो कमतर राष्ट्रवादी साबित करने की कोशिश तो जरूर की जा रही थी। यह कहना गलत नहीं होगा कि फर्जी राष्ट्रवाद के इस हल्ले से, विपक्ष भी कुछ समय तक तो हतप्रभ ही बना रहा था, जिसने संघ-भाजपा के इस हथियार को और मारक बना दिया। फिर भी, उन्मत्त राष्ट्रवादी दुहाई की आड़ में, चुनावी बढ़त बनाने का यह खेल इतनी नंगई से खेला जा रहा था कि जल्द ही इसके खिलाफ चारों तरफ से आवाजें उठने लगीं और विपक्ष की भी मूर्च्छा टूटी। अचरज नहीं कि खुद कई वरिष्ठ पूर्व-सैनिकों ने, सेना के नाम और उसकी कार्रवाई के प्रत्यक्ष राजनीतिक इस्तेमाल पर ही नहीं, सुरक्षा की चिंता के नाम पर युद्ध की पुकारों पर भी अपनी बेचैनी जतानी शुरू कर दी। ये पुकारें तो सिर्फ सुरक्षा के मुद्दों का राजनीतिक इस्तेमाल करने की कोशिश करती हैं और इस तरह सुरक्षा के मुद्दों पर जो सर्वानुमति रही भी है उसे भी तोड़कर, राष्ट्र को और असुरक्षित बनाने का ही काम करती हैं। बेशक, इसमें असुरक्षा का अनुपातहीन हौवा खड़ा कर, सुरक्षा बढ़ाने के वास्तविक प्रयासों का रास्ता रोकना या उन्हें मुश्किल बना देना भी शामिल है। कश्मीर, इसका जीता-जागता उदाहरण है कि कैसे सुरक्षा-सुरक्षा का जाप करने वाली मोदी सरकार ने, पांच साल में हालात को तेजी से बिगाड़कर, देश को असुरक्षित ही बनाया है। वायु सेना की जरूरत से बहुत कम लड़ाकू विमान खरीदे जाने और देश की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एचएएल से विमान बनाने का मौका छीनने वाले रफाल सौदे से लेकर, सुरक्षा के लिए वित्तीय संसाधनों की कमी पर मुरली मनोहर जोशी की अध्यक्षता वाली संसदीय कमेटी की रिपोर्ट तक, इसके साक्ष्यों की भरमार है कि मोदी राज में देश पहले से ज्यादा असुरक्षित ही हुआ है। देश की जनता भी अपने-अपने तरीके से इस सचाई को समझ रही है और सारे आसार इसी के हैं कि उन्मत्त राष्ट्रवाद का यह चुनावी हथियार, टीन की तलवार ही साबित होने जा रहा है। चुनाव की तारीखों के ऐलान से ऐन पहले आए चुनाव-पूर्व सर्वेक्षणों में, हफ्तों तक मैदान में लगभग अकेले ही इस तलवार को भांजते रहने के बावजूद, एनडीए का बहुमत के आंकड़े से पीछे ही छूटते नजर आना, इसी का महत्त्वपूर्ण संकेतक है। सी वोटर के सर्वे के अनुसार भी, एनडीए के 264 का आंकड़ा पार करने की संभावना नहीं है। याद रहे कि सीवोटर के ही जनवरी के सर्वे की तुलना में, राष्ट्रवाद के सारे दोहन के बावजूद, मार्च के सर्वे में एनडीए के खाते में सिर्फ 31 सीट की बढ़ोतरी दिखाई देती है और इसमें से भी ज्यादातर बढ़ोतरी, इसी दौरान महाराष्ट्र व तमिलनाडु में भाजपा द्वारा किए गए गठजोड़ों का ही नतीजा है। जैसे-जैसे जनता के वास्तविक हितों से जुड़े मुद्दे अपना असर दिखाएंगे, वैसे-वैसे फर्जी राष्ट्रवाद की तलवार और खुट्टल होती जाएगी। टीन की ही साबित होगी संघ परिवार की उन्मत्त राष्ट्रवाद की तलवार।

लेख चुनावी सर्वे में एनडीए बहुमत से दूर मगर सत्ता के पास

बाल मुकुन्द ओझा

आगामी लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को मिलेगा लोकतंत्र का ताज इसे लेकर न्यूज चैनलों पर घमासान शुरू हो गया है। लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही टीवी न्यूज चैनलों पर ओपिनियन पोल का जलवा शुरू हो गया है। देश की कई जानी मानीं सर्वे एजेंसियों ने न्यूज चैनलों के साथ मिलकर चुनावी सर्वे का आगाज कर दिया है। लोग भी अपने घरों पर बड़े चाव के साथ इन सर्वे परिणामों को देख कर वाद विवाद करने लगे हैं। टीवी चैनलों पर आ रहे चुनावी सर्वे पर विश्वास करें तो आगामी लोकसभा चुनाव में एनडीए ही जीत के करीब पहुँच कर सत्ता पर काबिज होगा। यूपीए अपनी स्थिति में पहले के मुकाबले सुधार अवश्य करेगा मगर मोदी विरोधी दलों के सहयोग के बावजूद सरकार बनाने में सफल नहीं होगा। इन सर्वे के मुताबिक निर्गुट पार्टियों के पास सत्ता की कुंजी होगी और वे जिसे चाहेंगे उसे लोकतंत्र का ताज पहनाएंगे। निर्गुट दलों के मोदी के पक्ष में जाने की संभावनाएं भी व्यक्त की जा रही हैं। आधा दर्जन टीवी चैनलों द्वारा कराये गए अलग अलग सर्वे में एबीपी सी-वोटर की ओर से किए गए सर्वे के मुताबिक एनडीए आम चुनाव में बहुमत से थोड़ा दूर रहेगा, लेकिन चुनाव बाद गठबंधन के जरिए आराम से सरकार बना लेगा। वहीं इंडिया टीवी और रिपब्लिक टीवी जैसे चैनल एनडीए के बहुमत की भविष्यवाणी कर रहे हैं। एबीपी न्यूज सी-वोटर, इंडिया टीवी सीएनएक्स, न्यूज नेशन, इंडिया टीवी, रिपब्लिक टीवी, टाइम्स नाउ - वीएमआर सहित आधा दर्जन चैनलों के सर्वे का निचोड़ देखें तो प्रधानमंत्री पद की पहली पसंद आज भी नरेंद्र मोदी बने हुए हैं। वहीं एनडीए पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले कमजोर स्थिति में है और यूपीए की स्थिति में सुधार परिलक्षित हो रहा है। एबीपी और न्यूज नेशन के सर्वे के विपरीत इंडिया टीवी- सीएनएक्स और रिपब्लिक टीवी के सर्वे में एनडीए को बहुमत मिलने का दावा किया गया है। सर्वे में सपा बसपा महा गठबंधन सहित टीएमसी, टीआरएस, वाईएसआर, बीजू जनता दल भी अपनी मजबूत पकड़ बनाये हुए है। इस बार नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर रखने के लिए विपक्ष एकजुट होने की कोशिश कर रहा है लेकिन अभी तक स्पष्ट नहीं है कि महागठबंधन की ओर से प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन होगा। विभिन्न न्यूज चैनलों के सर्वे के मुताबिक सत्ताधारी एनडीए को पिछले चुनाव के मुकाबले कम सीटें मिलेंगी लेकिन सबसे बड़े गठजोड़ के रूप में उभर कर बहुमत के करीब पहुंच सकता है। न्यूज चैनलों ने यह अनुमान लगाना भी शुरू कर दिया है की एनडीए लगभग 250 सीटें लाने के बाद अपनी सत्ता कैसे बरकरार रखेगा। चैनलों के मुताबिक बीजू जनता दल, टीआरएस और वाईएसआर के सहयोग से एनडीए एक बार फिर सत्ता पर काबिज हो सकता है। ऐसा होता है तो नरेंद्र मोदी आराम से दोबारा प्रधानमंत्री बन सकते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने सपा और बीएसपी का सूपड़ा साफ कर दिया था। बीजेपी ने 71 और सहयोगी अपना दल ने 2 सीटें जीती थीं।

लेकिन इस बार बीजेपी से टकराने के लिए एसपी और बीएसपी साथ आ गए हैं। उत्तर प्रदेश पर सबकी निगाहें लगीं हुईं हैं यहां काफी दिलचस्प अनुमान सामने आ रहा है यहां पर महागठबंधन को भारी बढ़त मिलती दिख रही है। महागठबंधन को यूपी की 80 सीटों में से 40 से 50 सीटें मिलती दिख रही हैं वहीं एनडीए को 30 से 40 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है यूपीए को 2 सीटों पर ही संतोष करना पड़ सकता है। सर्वे के अनुसार इसकी भरपाई पश्चिम बंगाल और उत्तर-पूर्व के राज्यों से होती दिख रही है। एबीपी और सी-वोटर के सर्वे में 543 लोकसभा सीट के लिए होने वाले चुनाव में भाजपा की अगुआई वाले एनडीए को 264 सीट मिलती नजर आ रही है। जबकि यूपीए 141 सीट पर जीत हासिल कर सकती है। अन्य पार्टियों को 138 सीट मिलने की संभावना है। न्यूज नैशन प्रोजक्शन के सर्वे में एनडीए को 268 से 272, यूपीए को 132 से 136 और अन्य को 137 से 141 सीटें दी गई हैं। इंडिया टीवी- सीएनएक्स और रिपब्लिक टीवी के सर्वे में एनडीए को बहुमत मिलने का दावा किया गया है। तमाम सर्वे में प्रधान मंत्री मोदी मतदाताओं की आज भी पहली पसंद बने हुए हैं। अन्य सर्वे में भी यूपीए की ताकत में इजाफा बताया गया है मगर सत्ता की चाबी के नजदीक एनडीए को बताया गया है। सर्वे के मुताबिक नवीन पटनायक, केसीआर और जगन रेड्डी को किंगमेकर के रूप में दर्शाया गया है। चुनाव बाद इन तीनों के मोदी के पक्ष में जाने की अधिक संभावनाएं व्यक्त की गयी हैं।

आज का राशीफल

मेष आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। यात्रा में अपने बहुमूल्य सामान के प्रति सचेत रहें चोरी या खोने की आशंका है। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। भाई या पड़ोसी का सहयोग रहेगा।

वृषभ व्यावसायिक योजना सफल होगी। पिता या उच्चाधिकारी का सहयोग मिलेगा। त्वचा उदर या वायु विकार की संभावना है। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी।

मिथुन जीवनसाथी का सहयोग व सानिध्य मिलेगा। उपहार व सम्मान का लाभ मिलेगा। किया गया प्रयास सफल होगा। यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद व लाभप्रद होगी। परिश्रम अधिक करना होगा।

कर्क पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। धन, पद, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। नए अनुबंध प्राप्त होंगे। किसी बहुमूल्य वस्तु के पाने की अभिलाषा पूरी होगी। जीवनसाथी का सहयोग व सानिध्य मिलेगा। व्यर्थ की भागदौड़ रहेगी।

सिंह पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। उदर विकार या त्वचा के रोग से पीड़ित रहेंगे। आय और व्यय में संतुलन बना कर रखें। मनोरंजन के अवसर प्राप्त होंगे। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी।

कन्या व्यावसायिक व पारिवारिक योजना सफल होगी। उपहार व सम्मान का लाभ मिलेगा। भाई या पड़ोसी से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आयेगी। अनचाही यात्रा या विवाद में फंस सकते हैं।

तुला बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। रुपए पैसे के लेन देन में सावधानी अपेक्षित है। विरोधी शारीरिक या मानसिक रूप से कष्ट देंगे। पारिवारिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। पिता या संबंधित अधिकारी से तनाव मिलेगा।

वृश्चिक पारिवारिक कार्यों में व्यस्त रहेंगे। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद व लाभप्रद होगी। मैत्री संबंध में प्रगाढ़ता आयेगी।

धनु शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में आशातीत सफलता मिलेगी। धन, पद, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। रुका हुआ कार्य सम्पन्न होगा। छोटी-छोटी बातों पर उत्तेजना हो सकती है। प्रणय संबंध प्रगाढ़ होंगे।

मकर रोजी रोजगार की दिशा में प्रगति होगी। उपहार व सम्मान का लाभ मिलेगा। नेत्र विकार की संभावना है। पिता या उच्चाधिकारी का सहयोग मिलेगा। रोग और विरोधी बढ़ेंगे। रुपए पैसे के लेन देन में सावधानी रखें।

कुम्भ पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। चली आ रही समस्याओं का समाधान होगा। संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा। व्यावसायिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। क्रोध व भावुकता में लिया गया निर्णय कष्टकारी होगा।

मीन जीवनसाथी का सहयोग व सानिध्य मिलेगा। आय और व्यय में संतुलन बना कर रखें। उदर विकार या त्वचा के रोग से पीड़ित रहेंगे। यात्रा देशाटन की स्थिति सुखत व लाभप्रद होगी। वाहन प्रयोग में सावधानी अपेक्षित है।

विश्व कप की दावेदारी को कमजोर करने वाली हार

शिवेंद्र कुमार सिंह वरिष्ठ खेल पत्रकार

कंगारुओं ने 2009 के बाद पहली बार भारत को उसी के घर में हरा दिया। फिरोजशाह कोटला मैदान में 273 रनों के लक्ष्य को हासिल करने में टीम इंडिया 237 पर ही सिमट गई। इस तरह ऑस्ट्रेलिया ने 35 रनों की जीत हासिल की। 2009 के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि ऑस्ट्रेलिया ने भारत को लगातार तीन वनडे मैचों में मात दी। कोहली की कप्तानी में पहली बार ऐसा हुआ कि उन्हें तीन मैचों में लगातार हार का सामना करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया ने करीब दो साल बाद कोई वनडे सीरीज जीती। जिस ऑस्ट्रेलियाई टीम का 2018 के बाद से वनडे मैचों में जीत का प्रतिशत 20 फीसदी से भी कम पर पहुंच गया था, वह लगातार मैच जीत गई। ऑस्ट्रेलिया ने रांची, मोहाली और दिल्ली में जो तीन वनडे मैच जीते, तीनों में उसकी जीत बहुत प्रभावी थी। उन्होंने भारतीय पिचों को ज्यादा बेहतर ढंग से समझा। उनके स्पिन गेंदबाजों को भारतीय स्पिनर्स के मुकाबले ज्यादा सफलता मिली। यह सब तब हुआ, जब आईसीसी की वनडे रैंकिंग में भारत ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले कहीं बेहतर स्थिति में था। हाल ही में उसने ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर में वनडे और टेस्ट सीरीज में हराया था।

इस सीरीज के पहले टीम इंडिया कागज और मैदान, दोनों पर ऑस्ट्रेलिया से कहीं बेहतर दिख रही थी। विश्व कप की तैयारियों के मद्देनजर भी भारत का दावा सबसे ज्यादा मजबूत था। ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले तो कहीं ज्यादा मजबूत, क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई टीम पिछले दो साल में न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज गंवाकर 'बैकफुट' पर थी। वनडे सीरीज के पहले मैच में कंगारुओं ने सिर्फ 236 रन बनाए। इसके बाद अगले मैच में ऑस्ट्रेलियाई टीम सिर्फ 251 रनों के लक्ष्य का पीछा नहीं कर पाई। इससे उलट अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में न उतरने के बाद भी भारतीय टीम को जीत मिली। बाजी पलटी तीसरे वनडे से। सीरीज में पहली बार ऑस्ट्रेलियाई टीम 300 रन के आंकड़े को पार करने में कामयाब हुई। इसके बाद तो भारतीय बल्लेबाजी की कमजोरी परत-दर-परत दिखने लगी। ऑस्ट्रेलिया ने वह मैच 32 रनों से जीता। अगले मैच में जब भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करते हुए 400 रनों के आस-पास पहुंचने का मौका मिला, तो वह 358 ही बना पाई। ऑस्ट्रेलिया ने यह लक्ष्य 13 गेंद पहले ही हासिल कर लिया। आखिरी मैच में भी भारतीय बल्लेबाजी का बुरा प्रदर्शन दिखाई दिया। लिहाजा पांच मैचों की सीरीज के खत्म होते-होते ऑस्ट्रेलियाई टीम भारतीय टीम के मुकाबले ज्यादा संतुलित दिखी। उसने यह संदेश भी दे दिया कि विश्व कप के लिए उसका दावा कमजोर न समझा जाए। विश्व कप के 11 संस्करणों में ऑस्ट्रेलियाई टीम ही पांच बार विजेता रही है। आखिर कैसे टीम इंडिया एक के बाद एक तीन मैच हार गई? इसके कई कारण हैं। इन कारणों में ही टीम इंडिया के लिए सबक भी छिपा हुआ है। अव्वल कारण है टीम का संतुलन। विश्व कप की तैयारियों के मद्देनजर कई खिलाड़ियों को आजमाने की कोशिश में टीम का संतुलन लगातार बनता-बिगड़ता रहा। टीम के करिश्माई स्पिनर्स की जोड़ी के तौर पर यजुवेंद्र चहल और कुलदीप यादव बेरंग दिखे। एक को छोड़कर बाकी चार मैचों में टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर ने लगातार निराश किया। नंबर चार के बल्लेबाज की परेशानी बनी रही। भारतीय बल्लेबाज ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर एडम जैंपा के खिलाफ बहुत असहज दिखाई दिए, जिसमें दुनिया के सबसे शानदार बल्लेबाज भारतीय कप्तान विराट कोहली भी शामिल हैं। टी-20 और वनडे सीरीज में उन्होंने तीन बार विराट कोहली को आउट किया। एडम जैंपा ने वनडे सीरीज में 11 विकेट लिए। इसके अलावा बड़ा सवाल यह भी है कि आखिरी दो वनडे मैचों में धौनी समेत पूरी सीरीज में जिन खिलाड़ियों को आराम दिया गया, वह नीति भी क्या दुरुस्त थी? अगले कुछ दिनों में ये खिलाड़ी आईपीएल में व्यस्त हो जाएंगे। आईपीएल के बाद टीम विश्व कप के लिए इंग्लैंड रवाना हो जाएगी। लेकिन भूलिएगा मत, कुछ समय पहले तक विश्व कप पर भारतीय टीम का जो दावा बहुत मजबूत दिख रहा था, उसे इस सीरीज के नतीजे ने कमजोर किया है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

त्योहारी मांग और बारिश से आलू के दाम में उछाल

लखनऊ।

त्योहारी और सहालग की मांग के चलते आलू की कीमतों में तेजी आई है। हालांकि इस तेजी का फायदा किसानों से ज्यादा आढ़तियों और थोक विक्रेताओं को हो रहा है। बीते पांच दिनों में खुदरा बाजार में आलू की कीमत 30 से 50 फीसदी बढ़ी है और मांग में भी तेजी आई है। खुदरा बाजार में अब तक 8 से 10 रुपए किलो बिकने वाला आलू इन दिनों 12 से 15 रुपए किलो बिकने लगा है। आलू कीमतों में तेजी कुछ दिन बने रहने की उम्मीद है। थोक कारोबारियों का कहना है कि प्रदेश सरकार अगले महीने से आलू की सरकारी खरीद शुरू कर देगी जिससे किसानों को अच्छा भाव मिलने लगेगा। आलू की सरकारी खरीद 549 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर की जाएगी। बीते साल भी सरकार ने आलू का न्यूनतम समर्थन मूल्य यही रखा था जिससे पूरे साल कीमतें ज्यादा नहीं गिरी थीं। राजधानी लखनऊ की थोक मंडी दुबग्गा के कारोबारियों का कहना है कि मार्च में महीने भर की सहालग और अब होली के चलते इन दिनों भाव तेज हुए हैं। हालांकि इस बार आलू की भारी पैदावार हुई है। उद्यान विभाग के अनुमानों के मुताबिक इस साल प्रदेश में 162 लाख टन आलू पैदा होगा जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। कारोबारियों का कहना है कि फरवरी में खुदाई शुरू होने पर कुछ दिन आलू की कीमतें गिरीं पर जल्दी ही संभल भी गईं। फरवरी में आलू के दाम गिरने के बाद मचे हो हल्ले के चलते प्रदेश सरकार ने कुछ कदम उठाए जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करना, बाहर के प्रदेशों में बेचने पर भाड़े की सब्सिडी और सरकारी खरीद शामिल था। पहले से उलट प्रदेश का आलू बाहर भी जाने लगा है। साथ ही सरकारी खरीद होने से भी कीमत संभल जाएगी। प्रदेश सरकार बीते दो सालों से आलू की सरकारी खरीद करने लगी है। वाराणसी में दो दिन पूर्व जहां आलू 8 से 10 रुपए किलो बिक रहा था, वहीं अब इसका खुदरा भाव 11 से 12 रुपए किलो तक पहुंच गया है जबकि 20 से 22 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिकने वाला मटर अब 32 रुपए के पार पहुंच गया है। दस रुपए किलो वाला टमाटर 30 से 35 रुपए किलो बिक रहा है। पूर्वांचल की सबसे बड़ी मंडी पहाड़िया के कारोबारी मोहम्मद ने बताया कि सभी सब्जियों के दाम में तेजी आई है। पहले बारिश और फिर होली के मद्देनजर बाजार में सब्जियों के भाव बढ़ गए हैं।

रेलवे ने यात्रियों को दिया होली का तोहफा, तत्काल टिकट बुकिंग में किया बड़ा बदलाव

नई दिल्ली ।

रंगों का त्योहार होली पर घर जाने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने बड़ा तोहफा दिया है।रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग में बदलाव किया है, जिसके बाद यात्रियों को तत्काल टिकट बुक कराना आसान हो जाएगा। आईआरसीटीसी ने तत्काल टिकट बुकिंग की अवधि को कम कर दिया है और इसमें कुछ बदलाव भी किए हैं। आईआरसीटीसी के मुताबिक, ट्रेन के चलने की जगह से सफर के दिन को छोड़कर तत्काल टिकट बुकिंग की एडवांस रिजर्वेशन पीरियड को दो दिनों से घटाकर एक दिन किया जा रहा है। अब ट्रेन के प्रस्थान करने की तारीख से एक दिन पहले तत्काल ट्रेन टिकट बुक किया जा सकता है। एसी क्लास के लिए तत्काल टिकट विंडो सुबह 10 बजे खुलती है, जबकि स्लीपर क्लास के लिए तत्काल विंडो सुबह 11 बजे खुलती है। आईआरसीटीसी के तत्काल टिकटों को एक पीएनआर से अधिकतम चार यात्रियों के लिए बुक किया जा सकता है। भारतीय रेलवे महिला और सामान्य कोटा के साथ तत्काल कोटा और ट्रेन टिकट की अनुमति नहीं देता है। साथ ही फर्स्ट एसी और एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए ये टिकट बुक नहीं किए जा सकते हैं। भारतीय रेलवे ने तत्काल टिकट के तहत स्लीपर क्लास के लिए ट्रेन टिकट बुक करने के लिए कम से कम 100 रुपये और अधिकतम 200 रुपये का शुल्क तय किया है। एसी चेयर कार टिकट के लिए भारतीय रेलवे द्वारा लगाए गए शुल्क 125-225 रुपये हैं। आप तत्काल टिकट को आईआरसीटीसी की वेबसाइट के अलावा रिजर्वेशन काउंटर से भी बुकिंग कर सकते हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक ने उठाया बड़ा कदम,सरकारी बैंक हो गया है प्राइवेट

मुंबई।

भारतीय रिजर्व बैंक ने आईडीबीआई बैंक को निजी क्षेत्र के बैंक की श्रेणी में रख दिया है। भारतीय जीवन बीमा निगम के आईडीबीआई बैंक में बहुलांश हिस्सेदारी के अधिग्रहण के बाद यह कदम उठाया गया है। एलआईसी ने आईडीबीआई में 51 प्रतिशत हिस्सेदारी के अधिग्रहण का काम जनवरी में पूरा किया। आईडीबीआई बैंक में चुकता शेयर पूंजी का 51 प्रतिशत अधिग्रहण के बाद बैंक को निजी श्रेणी में डाला गया है एलआईसी के आईडीबीआई बैंक में 51 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने से कर्ज के बोझ से दबे बैंक को करीब 10,000 करोड़ से 13,000 करोड़ रुपए का पूंजी समर्थन मिला। एलआईसी सार्वजनिक क्षेत्र की आईडीबीआई बैंक में बहुलांश हिस्सेदारी खरीदकर बैंकिंग क्षेत्र में उतरने की तैयारी कर रही थी। बैंक की दबाव वाली संपत्तियों के बावजूद इससे उसे कारोबारी तालमेल मिलेगा।

एलआईसी को करीब 2,000 शाखाएं उपलब्ध होंगी जिनके जरिए वह अपने उत्पाद बेच सकेगी। वहीं बैंक को एलआईसी से भारी कोष मिलेगा। इस सौदे से बैंक को करीब 22 करोड़ पालिसीधारकों के खाते और कोष का प्रवाह मिलेगा।

अप्रत्यक्ष कर लक्ष्य से चूकेगी सरकार, पर राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पूरा करेगी : गर्ग

मुंबई।

वित्त सचिव एस सी गर्ग ने बृहस्पतिवार को यह स्वीकार किया कि सरकार चालू वित्त वर्ष में अप्रत्यक्ष कर संग्रह का लक्ष्य संभवतः हासिल नहीं कर पाएगी लेकिन प्रत्यक्ष कर संग्रह के लक्ष्य को हासिल कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद वित्त वर्ष 2018- 19 के लिए रखे गए राजकोषीय घाटे के संशोधित 3.4 प्रतिशत के लक्ष्य को हासिल कर लिया जाएगा। माल एवं सेवा कर (जीएसटी) दरों में कई बार कटौती और छूट सीमा बढ़ाए जाने की वजह से जीएसटी संग्रह में गंभीर गिरावट दिख रही है। इस साल में केवल कुछ ही महीनों में जीएसटी संग्रह लक्ष्य के मुताबिक एक लाख करोड़ रुपये के पार गया। इस वित्त वर्ष में जीएसटी अब तक औसतन 95,000 करोड़ रुपए मासिक रहा है। गर्ग ने फिक्की-आईबीए के कार्यक्रम के मौके पर संवाददाताओं से अलग से बातचीत में कहा, ''प्रत्यक्ष कर के मोर्चे पर हम काफी हद तक आशान्वित हैं। हालांकि, अप्रत्यक्ष कर संग्रह लक्ष्य से कुछ कम रहेगा।'' हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि अप्रत्यक्ष कर संग्रह लक्ष्य से कितना कम रहेगा। गर्ग ने कहा, ''हम इसकी भरपाई बचत से कर लेंगे। ऐसे में 3.4 प्रतिशत का राजकोषीय घाटे का लक्ष्य सुरक्षित है।'' सरकार ने अंतरिम बजट में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 3.4 प्रतिशत रहने का संशोधित लक्ष्य रखा है जो पिछले बजट में रखे गए लक्ष्य की तुलना में 0.1 प्रतिशत अधिक है। यह लगातार दूसरा वर्ष रहा है जब मोदी सरकार राजकोषीय घाटे के बजट लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाई। सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान प्रत्यक्ष करों से 12 लाख करोड़ रुपए रहने का लक्ष्य तय किया है। इससे पहले इसके 11.50 लाख करोड़ रुपए रहने का बजट अनुमान रखा गया था। गर्ग ने कहा कि वित्त मंत्रालय के अधिकारी 26 मार्च को रिजर्व बैंक के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात कर पहली छमाही के लिए बाजार से उधारी की समयसारीणी तैयार करेंगे।

संक्षिप्त समाचार

पेटीएम वॉलेट में रखे पैसों पर भी मिलेगा 4 प्रतिशत का ब्याज और भी फायदे

बिजनेस डेस्क । पेटीएम से लेन-देन करने पर आपको 4 प्रतिशत का सेविंग अकाउंट का ब्याज मिलेगा। यदि जमा राशि एक लाख रुपए से ज्यादा है तो यह अपने आप भी फिक्स डिपोजिट ( ) में बदल जाएगी। इससे आपको बैंकों से भी ज्यादा 8 प्रतिशत की ब्याज दर का फायदा मिलेगा। यही नहीं, आप जब चाहे इस एफडी को बिना किसी चार्ज के ही तुड़वा सकते हैं। यह संभव हुआ है पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (पीपीबी) के नई मोबाइल बैंकिंग एप की लांचिंग से। पेटीएम ने ऐसा कर सीधे तौर पर भारतीय बैंकिंग सर्विस में अपनी पैठ बनाने की कोशिश शुरू कर दी है। नए एप मौजूदा पेटीएम एप से अलग है। गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड किया जा सकता है। जल्द ही एप्पल एप स्टोर पर भी उपलब्ध होगा। इस एप के जरिए आप सरलता से बैंकिंग सेवाओं का उपयोग कर सकेंगे। यह डिजिटल डेबिट कार्ड आदि के उपयोग करने की सुविधा देगा। मोबाइल बैंकिंग ऐप के माध्यम से बैलेंस चेक, अकाउंट स्टेटमेंट व 24×7 सहायता भी प्राप्त कर सकेंगे। मई 2017 में पेटीएम बैंक लांच हुआ था। अभी पेटीएम के 4.3 करोड़ उपभोक्ता हैं। इन सभी को वर्चुअल डेबिट कार्ड दिया गया है। एप में सिर्फ एक क्लिक से डेबिट कार्ड के दुरुपयोग से सुरक्षित करने की सुविधा है। इस अवसर पर पेटीएम पेमेंट्स बैंक के एमडी व सीईओ सतीश कुमार गुप्ता ने कहा कि नया एप अपने बैंक के ग्राहकों के लिए चरणबद्ध तरीके से बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए पेश किया गया है। नए एप का उद्देश्य मौजूदा एप से अपने संचालन को अलग करना है। इससे दूसरी संस्थाओं में ग्राहकों को बैंकिंग करने में आसानी होगी।

कोल इंडिया ने की दूसरे अंतरिम लाभांश की घोषणा

नई दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र की कोल इंडिया लिमिटेड के निदेशक मंडल ने 2018-19 के लिए दूसरी बार अंतरिम लाभांश की घोषणा की। कंपनी प्रति शेयर 5.85 रुपए का अंतरिम लाभांश देगी। शेयर बाजार को दी जानकारी में कंपनी ने बताया कि 14 मार्च को उसके निदेशक मंडल की बैठक में वित्त वर्ष 2018-19 के लिए दूसरे अंतरिम लाभांश को मंजूरी दे दी गई। इसके तहत कंपनी 10 रुपए अंकित मूल्य के प्रति शेयर पर 5.85 रुपए का अंतरिम लाभांश देगी। कंपनी इस अंतरिम लाभांश का भुगतान 29 मार्च को करेगी।

उड़ानें रद्द होने से यात्रियों की बढ़ी मुश्किलें, डबल हुआ किराया

नई दिल्ली/मुंबई । सरकार के 737 मैक्स विमान के परिचालन को रोके जाने और कई अन्य कारणों से कई विमानन कंपनियों द्वारा परिचालन रद्द किए जाने से हवाई यात्रियों को अधिक हवाई किराए और कम विमान विकल्प की विकट संभावनाओं का सामना करना पड़ रहा है। उद्योग सूत्रों के मुताबिक, अंतिम क्षणों में बुकिंग कराने में कुछ सेक्टरों में 100 फीसदी से ज्यादा की वृद्धि देखी गई है। इक्सिगो के सीईओ और सह-संस्थापक आलोक बाजपेई ने कहा, विभिन्न कारकों से बड़ी संख्या में विमानों का परिचालन रुका हुआ है और इससे सीट क्षमता में कमी आई है, जिससे रातोंरात में विमान किराए में वृद्धि हुई है। दिल्ली-मुंबई, मुंबई-चेन्नई, मुंबई कोलकाता और मुंबई-बेंगलुरू जैसे मुख्य मार्गों पर हवाई किराए में पिछले साल इस वक्त की तुलना में बुधवार को अंतिम क्षणों में बुकिंग कराने में 100 फीसदी से ज्यादा की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा, मुंबई-चेन्नई के लिए मौजूदा किराया 26,073 रुपये पहुंच गया है जबकि पिछले साल इसी अवधि में किराया 5,369 रुपये था। बढ़ती मांग के परिणामस्वरूप होली और गर्मियों की छुट्टियों के नजदीक होने से अधिक हवाई किराए के बने रहने की उम्मीद है। इथियोपिया में दुर्घटना के बाद भारत सरकार ने बुधवार को 737 मैक्स विमान का परिचालन रोकने का फैसला किया था जिससे स्पाइसजेट और जेट एयरवेज जैसी विमानन कंपनियों का परिचालन काफी प्रभावित हुआ। भारत में स्पाइसजेट 12 व जेट एयरवेज पांच 737-800 मैक्स विमानों का परिचालन करता है। जेट फ्लीट का एक हिस्सा अन्य कारणों से भी उड़ान नहीं भर पा रहा है। परिचालन रोके जाने से स्पाइसजेट को बुधवार को 14 उड़ानों को रद्द करना पड़ा। गुरुवार को इसकी संख्या 32 तक पहुंच सकती है। स्पाइसजेट के अलावा वित्तीय चुनौतियों का सामना कर रहे जेट एयरवेज के पहले से ही चार विमान परिचालन से बाहर हैं। ये चार विमान पट्टाकर्ताओं की बकाया राशि का भुगतान नहीं किए जाने के कारण परिचालन से बाहर हैं, ।

14 वर्ष से मार्क जकरबर्ग के खास सिपहसालार रहे क्रिस कॉक्स ने दिया इस्तीफा

कैलिफॉर्निया । फेसबुक के चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर क्रिस कॉक्स ने इस्तीफा दे दिया है। कंपनी के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने गुरुवार को इसका ऐलान किया। कॉक्स फेसबुक के उन प्रमुख अधिकारियों में से एक थे जो जकरबर्ग के काफी खास व भरोसेमंद थे। जकरबर्ग का कहना है कि कॉक्स ने फेसबुक के न्यूज फीड जैसे प्रमुख प्रोडक्ट पर काम किया था। उन्होंने फेसबुक ऐप की जिम्मेदारी भी संभाली थी। हाल ही में वो कंपनी के सभी ऐप्स की स्ट्रैटजी देख रहे थे। कॉक्स कंपनी के शुरुआती 15 इंजीनियरों में से एक थे। उन्होंने फेसबुक की शुरुआत के एक साल बाद यानी 2005 में फेसबुक ज्वॉइन की थी। कॉक्स के इस्तीफे की वजह फिलहाल साफ नहीं हो पाई है। कयास यह भी लगाए जा रहे हैं कि कंपनी की नीतियों को लेकर कॉक्स के जकरबर्ग से मतभेद हो सकते हैं। उन्होंने फेसबुक पोस्ट के जरिए कंपनी की नई योजना को लेकर लिखा है कि यह बड़ा प्रोजेक्ट होगा और हमें ऐसे लीडर्स की जरूरत होगी जो नई दिशा-निर्देशों के लिए उत्साहित हों।

जीएसटी दरें घटने के बावजूद मकान सस्ता नहीं होने की चेतावनी दे रहे हैं डिवेलपर्स

नई दिल्ली।

अंडर-कंस्ट्रक्शन मकानों पर जीएसटी की दरों में भारी कटौती के बावजूद इनकी कीमतों में बहुत ज्यादा गिरावट की उम्मीद नहीं की जा रही है। इनपुट टैक्स क्रेडिट से वंचित रियल एस्टेट सेक्टर ने जहां सीमेंट और स्टील जैसे इनपुट मटीरियल पर जीएसटी की ऊंची दरों पर चिंता जताई है। पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स ऐंड इंडस्ट्री की ओर से रियल एस्टेट में इनपुट क्रेडिट की विसंगतियों पर गुरुवार को आयोजित एक कॉन्फ्रेंस में इंडस्ट्री ने शीर्ष अधिकारियों से कहा कि अगर ये मुद्दे हल नहीं हुए, तो आम ग्राहक को सस्ते मकान दिलाने की कोशिशें रंग नहीं लाएंगी। काउंसिल की पिछली बैठक में अंडर-कंस्ट्रक्शन मकानों पर जीएसटी दरें बिना क्रेडिट के 5 फीसदी और अफोर्डेबल हाउसिंग पर 1 फीसदी कर दी गईं थीं यानी कच्चे माल की खरीद पर चुकाए गए टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा। उद्योग के प्रतिनिधियों ने कहा कि लागत के सबसे बड़े हिस्से सीमेंट पर जीएसटी रेट 28 फीसदी है। अगर क्रेडिट नहीं मिलेगा तो बिल्डर इसका बोझ ग्राहक पर डालेंगे। मेट्रो और नॉन-मेट्रो शहरों के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग की डेफिनिशन पर भी सवाल उठाए गए और कहा गया कि दिल्ली-मुंबई में 45 लाख में 60 वर्गमीटर तक मकान देना मुश्किल है। पीएचडी चैंबर की इनडायरेक्ट टैक्स कमिटी के चेयरमैन बिमल जैन ने कहा, एक चुनौती यह भी है कि बिल्डर के पास अब तक जो इनपुट क्रेडिट उपलब्ध है,।

वह 1 अप्रैल को लैप्स हो जाएगा, जबकि इंडस्ट्री चाहती है कि इसे कैरी फॉरवर्ड करने की छूट मिले। जो बिल्डर रेजिडेंशल के साथ कमर्शल कंस्ट्रक्शन भी करते हैं, उनके लिए कई बुक्स और अकाउंट मेंटेन करने की जटिलता आ जाएगी, क्योंकि एक मकान पर आईटीसी मिलेगा और दूसरे पर नहीं।

पीएचडी धारकों के लिए ब्रिटेन ने खोले दरवाजे, भारतीयों को होगा फायदा

लंदन।

ब्रिटेन ने पीएचडी-लेवल के वर्क वीजा जारी करने की संख्या असीमित करने का फैसला लिया है। ब्रिटेन सरकार की इस नई योजना से भारतीय पेशेवर लाभान्वित होने वाला सबसे बड़ा समूह होगा। ब्रिटेन के चांसलर फिलिप हैमंड ने बुधवार को बजट अपडेट में यह घोषणा की। उन्होंने कहा, 'इस साल के अंत से उच्च शिक्षित लोगों के ब्रिटेन आने की संख्या कुछ शर्तों के साथ असीमित होगी। वे ब्रिटेन में काम करने के लिए आवेदन कर सकते हैं।' हैमंड ने हाउस ऑफ कॉमन्स को संबोधित करते हुए बताया, ब्रिटेन को तकनीकी क्रांति के अगुआ बनाए रखना हमारी योजना का प्रमुख स्तंभ है। इससे हमारी अर्थव्यवस्था का कायाकल्प हो रहा है और इस लक्ष्य को साधने लिए पतझड़ के मौसम से हम पीएचडी लेवल की नौकरियों के लिए वीजा की संख्या की सीमा खत्म कर देंगे। उन्होंने अपने बयान में कहा, ऑटम 2019 से पीएचडी स्तर की नौकरियों को टियर 2 (जनरल) की सीमा से मुक्त कर देंगे और उसी वक्त 180 दिनों की अनुपस्थिति से संबंधित आव्रजन कानून (इमिग्रेशन रूल्स) भी बदल दिए जाएंगे ताकि विदेशों में फील्डवर्क करने वाले रिसर्चर यूके में रहना चाहें तो उन्हें परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। यूके के गृह मंत्रालय के बिल्कुल ताजातरीन आंकड़ों के मुताबिक 2018 में उच्च कौशल की नौकरियों के लिए 54 प्रतिशत टियर 2 (जनरल) श्रेणी के वर्क वीजा भारतीयों को दिए गए थे। पिछले साल भारतीयों को इस कैटिगरी के वीजा की स्वीकृति में भी सबसे बड़ी वृद्धि दर्ज की गई। आंकड़े बताते हैं कि 2017 के मुकाबले 2018 में भारतीयों को 6 प्रतिशत यानी 3,023 ज्यादा वीजा मिले। अभी यूके के वीजा सिस्टम में टियर 2 स्किल्ड वर्कर्स सेक्शन के तहत सीमित संख्या में वीजा जारी किए जाते हैं। यूके की सरकार 2021 तक नया इमिग्रेशन सिस्टम लागू कर स्किल्ड वर्कर्स के लिए वीजा की संख्या की सीमा पूरी तरह खत्म करना चाहती है। पीएचडी लेवल के प्रफेशनल्स के लिए वर्क वीजा पर से पाबंदी हटाने का ताजा ऐलान इसी दिशा में बढ़ाया गया पहला कदम माना जा रहा है। इसी साल इमिग्रेशन मिनिस्टर कैरोलिन नोक्स ने कहा था, %नए सिस्टम में हम भारत से बेहद कुशाग्र एवं सर्वोत्तम (पेशेवरों) का खुलकर स्वागत करेंगे।

रिलायंस जियो ने इस मामले में फिर मारी बाजी, सभी कंपनियों को पीछे छोड़ा

नई दिल्ली । मुकेश अंबानी की दूरसंचार कंपनी रिलायंस जियो ने 4जी डाउनलोड स्पीड के मामले में अपनी प्रतिस्पर्धी कंपनियों के मुकाबले फरवरी 2019 में भी अव्वल स्थान बनाये रखा। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) की तरफ से जारी नवीनतम आँकडों के अनुसार, फरवरी माह में जियो की औसत डाउनलोड स्पीड जनवरी के 18.8 एमबीपीएस की तुलना में बढ़कर 20.9 एमबीपीएस पर पहुँच गई जो इस क्षेत्र की अन्य कंपनियों की तुलना में दुगने से भी अधिक है। वर्ष 2018 में पूरे साल रिलायंस जियो इस मामले में अग्रणी रही थी। ट्राई के आँकडों के अनुसार, भारती एयरटेल की डाउनलोड स्पीड फरवरी में जनवरी के 9.5 एमबीपीएस की तुलना में घटकर 9.4 एमबीपीएस रह गई। वोडाफोन और आइडिया सेल्युलर के कारोबार का विलय हो चुका है और अब यह वोडाफोन-आइडिया के रूप में काम कर रही है किंतु ट्राई ने डाउनलोड और अपलोड स्पीड में दोनों का प्रदर्शन अलग-अलग दर्शाया है। वोडाफोन नेटवर्क की औसत 4जी डाउनलोड स्पीड जनवरी के 6.7 एमबीपीएस की तुलना में मामूली बढ़कर फरवरी में 6.8 एमबीपीएस हो गई। आइडिया की फरवरी में पहले के 5.5 एमबीपीएस की तुलना में 5.7 एमबीपीएस पर पहुंच गई। 4 जी अपलोड स्पीड के मामले में वोडाफोन ने आइडिया को पीछे छोड़कर अग्रणी स्थान हासिल किया। 4 जी अपलोड स्पीड के मामले में वोडाफोन ने आइडिया को पीछे छोड़कर अग्रणी स्थान हासिल किया। वोडफोन की 4जी अपलोड स्पीड जनवरी के 5.4 एमबीपीएस से बढ़कर फरवरी में छह एमबीपीएस हो गई। आईडिया और एयरटेल नेटवर्क की औसतन 4जी अपलोड स्पीड जनवरी की तुलना में मामूली गिरावट से फरवरी में क्रमश 5.6 और 3.7 एमबीपीएस रह गई। रिलायंस जियो ने इस क्षेत्र में भी पहले की तुलना में सुधार किया और फरवरी में उसकी 4जी अपलोड स्पीड 4.5 एमबीपीएस हो गई।

गेहूं का उत्पादन बढ़ने से किसान चिंतित, भाव कम मिलने का अंदेशा

नई दिल्ली ।

सर्दी के मौसम में विस्तार और मार्च के शुरू में बारिश ने इस साल गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन होने की उम्मीद जगाई है, मगर किसान इस बात से चिंतित है कि उत्पादन ज्यादा होने से उनको फसल का वाजिब दाम नहीं मिल पाएगा। कृषि विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस साल गेहूं का उत्पादन 10.5 करोड़ टन हो सकता है। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के पास फरवरी में 239.31 लाख टन गेहूं का भंडार था जबकि पिछले साल फरवरी में एजेंसी के भंडार में 175.47 लाख टन गेहूं था। इस साल भंडार ज्यादा होने से गेहूं की सरकारी खरीद को लेकर किसानों की चिंता बढ़ गई। अगर, सरकारी खरीद कम होती है तो गेहूं का बाजार भाव लुढ़क जाएगा जिससे किसानों को उनकी फसल का वाजिब दाम नहीं मिल पाएगा। केंद्र सरकार ने फसल वर्ष 2018-19 में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य पिछले साल से 105 रुपये बढ़ाकर 1,840 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। पंजाब के मानसा जिला स्थित बरेटा के किसान नजर सिंह ने कहा, अगर, सरकार ने समय पर खरीद शुरू नहीं की तो हमें बाजार भाव पर गेहूं बेचना पड़ेगा जोकि आपूर्ति ज्यादा होने कम हो सकता है। अधिकारियों ने बताया कि मध्यप्रदेश के कुछ इलाकों में गेहूं की कटाई शुरू हो चुकी है और अप्रैल के पहले सप्ताह से देशभर में गेहूं की कटाई शुरू हो जाएगी। किसान नेता केदार सिरोही ने कहा कि मौजूदा बाजार भाव के अनुसार बेहतर दाम मिलने की उम्मीद की जा सकती है लेकिन आपूर्ति बढ़ने पर आमतौर पर व्यापारियों की रणनीति बदल जाती है, इसलिए कीमतों में गिरावट आ सकती है। कृषि विशेषज्ञ देविंदर शर्मा ने कहा कि किसान ज्यादा फसल उपजाते हैं तो उतनी आय नहीं मिलती है जितनी वह उम्मीद करते हैं इसलिए सही दाम पाने के लिए उनको उत्पादन में कटौती करनी पड़ती है। उन्होंने कहा, अगर वे लाभकारी मूल्य चाहते हैं तो उनको उत्पादन में कम से कम 10 फीसदी कटौती करनी चाहिए। यह राष्ट्रविरोधी नहीं है। आखिर उनको आजीविका के लिए जद्दाजहद करनी पड़ती है। भारतीय गेहूं व जौ अनुसंधान केंद्र के निदेशक जी.पी. सिंह ने कहा कि इस साल 10 करोड़ टन से ज्यादा गेहूं का उत्पादन होने का सपना पूरा होगा। उन्होंने कहा, ÷सर्दी के मौसम में विस्तार और मार्च के पहले सप्ताह में बारिश होने से गेहूं के लिए मौसमी दशा अनुकूल हो गई, जिससे ज्यादा उत्पादन होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा, हमें उम्मीद है कि इस साल 10.5 करोड़ टन गेहूं का उत्पादन हो सकता है। हालांकि केंद्रीय कृषि मंत्रालय की ओर से पिछले महीने जारी फसल वर्ष 2018-19 की प्रमुख फसलों के दूसरे अग्रिम उत्पादन अनुमान के अनुसार, इस साल गेहूं का उत्पादन 991.2 लाख टन हो सकता है। चीन के बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है। पिछले साल के दूसरे अग्रिम उत्पादन अनुमान के अनुसार देश में गेहूं का उत्पादन 971.1 लाख टन था। पिछले साल सरकारी एजेंसियों ने 358 लाख टन गेहूं की खरीद की थी।

सूरत। अठवा गेट नागरिक सुविधा केन्द्र में स्वच्छता अभियान का उडाया जा रहा मजाक। सूरत महानगर पालिका के आफिसों में ही डस्टबीन का कोई बंदोबस्त नहीं है और सूरत महानगर पालिका सड़कों पर डस्टबीन लगा रही है। नागरिक सुविधा केन्द्र के अंदर ही कचरा इधर उधर बिखरा पड़ा फोटों में दिखाई दे रहा है।

राष्ट्रपति ने गुजरातियों की उद्यमिता की प्रशंसा की

राष्ट्र विकास में इनोवेशन की शक्ति का उपयोग करना जरूरी

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ग्रामभारती संस्था में १०वें राष्ट्रीय ग्रासरूट इनोवेशन पुरस्कार समारोह में उपस्थित

गांधीनगर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गांधीनगर निकट ग्रामभारती संस्था में १०वें राष्ट्रीय ग्रासरूट इनोवेशन और विशिष्ट पारंपारिक ज्ञान पुरस्कार समारोह में बताया कि, इनोवेशन द्वारा स्थानीय समस्या का स्थानीय स्तर पर समाधान मिलने की संभावना है। उन्होंने बताया कि, महात्मा गांधीजी के ग्राम स्वराज के अभियान के मूल में भी यही भावना थी।

राष्ट्रपति ने अपने संबोधन की शुरूआत गुजराती भाषा में करता केम छो यह प्रश्न पूछकर बताया कि, गुज राती लोग और गुजरात की व्यंजन में मीठाश होती है। राष्ट्रपति ने गुजरातियों की इनोवेशन और उद्यमिता की प्रशंसा की। उन्होंने बताया कि, हर बार यह पुरस्कार समारोह राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया जाता था। लेकिन इस

बार राष्ट्रपतिभवन के बाहर पहली बार यह समारोह आयोजित किया जा रहा है। जिसका श्रेय गुजरात को मिलेगा। गुज रात में यह कार्यक्रम आयोजित करने के संदर्भ में राष्ट्रपति ने बताया कि, गुजरात इनोवेशन और उद्यमिता की जन्मभूमि है इतना ही नहीं, इनोवेश के हिमायती राष्ट्रपति महात्मा गांधीजी की १५०वीं जयंती मनाई जा रही है तब यह समारोह आयोजित करने के लिए गुजरात की पसंदगी की गई है। राष्ट्र के सर्वांगीण विकास में इनोवेशन की शक्ति का ज्यादातर उपयोग करना जरूरी होने का बताते हुए राष्ट्रपति ने आगे बताया कि, इनोवेशन की महत्व को समझकर इसका उपयोग, स्वास्थ्य, शिक्षा, अन्न सुरक्षा, ऊर्जा उपलब्ध, पर्यावरण सुरक्षा तथा नेशनल सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में करना जरूरी है। जिसकी वजह से इनोवेशन्स का सामाजिक और आर्थिक लाभ राष्ट्र को मिल सके। इनोवेटिव आइडिया के लिए स्कूल स्तर से ही हमें शुरूआत करनी पड़ेगी यह बताकर राष्ट्रपति ने आगे बताया कि, स्कूल में रट्टा करने के बदले में विद्यार्थियों को जिज्ञासा का विकास करना और प्रश्नों को पूछने के लिए प्रेरित करना पड़ेगा। समस्याओं के समाधान के लिए विद्यार्थियों को प्रवृत्त करना पड़ेगा। नेशनल इनोवेशन फाउन्डेशन-इंडिया द्वारा इस क्षेत्र में हो रहे प्रयासों को उन्होंने ध्यान में लिया।

विभिन्न पार्टियों के चुनाव प्रचार के लिए साहित्य तैयार करने का काम चल रहा है।

गुजरात कांग्रेस की वेबसाइट हेक कर हार्दिक पटेल का अश्लील वीडियो पोस्ट

अहमदाबाद। गुजरात कांग्रेस की वेबसाइट हेक कर किसी ने हार्दिक पटेल का अश्लील वीडियो पोस्ट कर दिया और कहा कि हमारे नेता का स्वागत करें। इस घटना के बाद फिलहाल गुजरात कांग्रेस की वेबसाइट को बंद कर दिया गया है। कांग्रेस आईटी सेल के इन्चार्ज हेमांग रावल के मुताबिक कांग्रेस की वेबसाइट पर एरर आ रहा है। किसी ने वेबसाइट हेक कर अश्लील वीडियो पोस्ट किए हैं। फिलहाल हमने वेबसाइट बंद कर दी है। वेबसाइट कहां से हेक की गई, इसका आईपी एड्रेस मिलने के बाद मामला दर्ज करवाएंगे।

बेलगाम कार ने एक्टिवा को मारी टक्कर, किशोर की मौत, दो घायल

भरुच। भरुच कॉलेज पर एक बेलगाम ने टू व्हिलर को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में एक किशोर की मौत हो गई और 7 वर्षीय बच्ची व महिला घायल हो गई। घायलों को हिलिंगटच अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

जानकारी के अनुसार भरुच के लिंक रोड स्थित रंग अवधुत सोसायटी निवासी 38 वर्षीय रवि अरविंदभाई पटेल की 7 वर्षीय पुत्री केया का जन्म दिन था। मांगरोल कोर्ट में बतौर अधीक्षक सेवारत रवि पटेल बुधवार रात करीब साढ़े आठ बजे परिवार और झगडिया कोर्ट में सेवारत

आसिस्टन्ट पब्लिक प्रोसिक्युटर निहारिका प्राणभाई उमरिया के साथ भरुच कॉलेज रोड स्थित होटल आशीष में भोजन करने जा रहे थे। अलग अलग एक्टिवा पर सवार ये लोग गोवर्धन अस्पताल के निकट से गुजर रहे थे उस वक्त एक बेलगाम कार ने निहारिका के एक्टिवा को जोरदार टक्कर मार दी जिसमें केया, निहारिका और 11 वर्षीय वेदांत गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना के बाद मौके पर स्थानीय लोग जमा हो गए और घायलों को निजी वाहन के जरिए अस्पताल पहुंचाया। जहां डॉक्टर ने वेदांत को मृत घोषित कर दिया। जबकि निहारिका और केया की हालत नाजुक बनी हुई है। घटना के बाद भरुच सी डिवीजन पुलिस मौके पर पहुंच गई और दुर्घटना को अंजाम देनेवाली कार चालक समेत दो लोगों को गिर तार कर आगे की कार्यवाही शुरू की है।

शाह गुजरात से उतरेंगे चुनावी मैदान में, आडवाणी बनाएंगे रिकॉर्ड

अहमदाबाद। लोकसभा चुनाव का ऐलान होने के बाद अब हाई प्रोफाइल सीटों से उ मीदवारों के लड़ने की चर्चा शुरू हो गई है। इसी में शामिल गुजरात की गांधीनगर सीट को लेकर भी अटकलें तेज हो गई हैं। वर्तमान में इस सीट से पूर्व उप-प्रधानमंत्री और भाजपा के व ?रिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी सांसद हैं लेकिन 91 साल के होने की वजह से इस बार उनके चुनाव लड़ने की संभावनाएं नहीं दिख रही हैं। ऐसे में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का नाम इस सीट से सामने आ रहा है। गुजरात की गांधीनगर सीट भाजपा के लिए सबसे सुरक्षित सीटों में से एक है। साल 1989 में हुए लोकसभा चुनावों में भाजपा उ मीदवार शंकर सिंह वाघेला ने जीत दर्ज की थी, जिसके बाद इस सीट से भाजपा की जीत का सिलसिला अभी भी जारी है। वहीं, अमित शाह गांधीनगर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली नारणपुरा और सरखेज सीट से विधायक रह चुके हैं। सरखेज सीट से उन्होंने लगातार चार बार चुनाव जीता था हालांकि साल 2012 में सीट बदलते हुए शाह नारणपुरा की तरफ चले गए और वहां पर भी उन्होंने अपना विजयी रथ आगे बढ़ाया।

साल 2014 में हुए लोकसभा चुनावों में देश में नरेंद्र मोदी के नाम की लहर थी, जिसकी बदौलत बीजेपी ने गुजरात की सभी 26 लोकसभा सीटों पर कब्जा कर लिया था। हालांकि, अमित शाह को भाजपा ने गुजरात से राज्यसभा भेज दिया था। विशेषज्ञों की मानें तो अगर इस बार प्रधानमंत्री मोदी गुजरात से चुनाव नहीं लड़ते हैं तो अमित शाह ही वो कड़ी होंगे जो गुजरात में कार्यकर्ताओं के जोश को बरकरार रख सकते हैं।

चुनावों से पहले ऐसी खबरें आ रही थीं कि राजनीतिक पार्टियां इस बार अपने वरिष्ठतम नेताओं को चुनाव में नहीं उतारेगी लेकिन कांग्रेस द्वारा सोनिया गांधी को टिकट दिए जाने के बाद से राजनी ?तिक हलकों में चर्चा है ?कि लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे कद्दावर नेता भी चुनाव लड़ सकते हैं। अगर इस बार लालकृष्ण आडवाणी ने चुनाव लड़ा तो वो एक नया रिकॉर्ड बना देंगे। क्योंकि 91 साल की उम्र में अभी तक किसी भी सांसद ने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा है और वह ऐसा करने वाले पहले सांसद बन सकते हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता आडवाणी के पास तजुर्बा इतना है कि वह इस बार चुनाव न लड़ें तो भी रिकॉर्ड बनाएंगे।

एकजुट होकर लड़ने पाटीदार समाज को अपील

भाजपा की तानाशाही से परेशान रेशमा ने आखिर में पार्टी छोड़ी

हार्दिक पटेल को समर्थन देने की घोषणा : तानाशाही नेताओं की पाप की भागीदारी से मुक्त हो रही हूं : रेशमा

अहमदाबाद,१५ मार्च।

भाजपा के विरूद्ध खुलेआम कड़े प्रहार करने के लिए लोकप्रिय हुई पाटीदार महिला नेता और भाजपा में कुछ महीने शामिल हुई रेशमा पटेल ने भाज पा से परेशान होकर आखिर में शुक्रवार को अपना इस्तीफा दे दिया और भाजपा के साथ रिश्ता खत्म करने की आधिकारिक घोषणा कर दी।

रेशमा पटेल ने इसके साथ पाटीदार युवा हार्दिक पटेल को समर्थन देने की घोषणा करने के साथ भाजपा को हराने के लिए एकजुट होकर लड़ने के लिए पाटीदार समाज सहित सभी से अपील की। इतना ही नहीं रेशमा पटेल ने भाजपा और इसके नेताओं पर निशाना साधते हुए गंभीर आरोप भी लगाये। जिसे लेकर गुजरात की राजनीति में

हलचल तेज हो गई। रेशमा ने बताया कि, भाजपा के तानाशाही नेताओं की पाप की भागीदारी से घुटन महसूस हो रही है और इसी वजह से तानाशाही नेताओं की पाप की भागीदारी से मुक्त हो रही हूं। राज्य के सभी छोटे-बड़े पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लग गये हैं तब राज्य में भी चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है और भाजपा और कांग्रेस में चल रही आयाराम-गयाराम परिस्थिति के बीच पूर्व पास कन्वीनर और भाजपा की नेता रेशमा पटेल ने भाजपा से इस्तीफा देकर फिर से राजनीति हलचल तेज हो गई। रेशमा पटेल ने पोरबंदर लोकसभा के साथ माणावदर से विधानसभा भी लड़ने की इच्छा व्यक्त की। यदि कोई पार्टी टिकट नहीं दे तो निर्दलीय चुनाव लड़ूंगी। रेशमा पटेल ने शुक्रवार को राजकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित की। जि समें उसने बताया कि, भाजपा को हराने के लिए एकजुट होकर चुनाव लड़ना होगा। भाजपा से मैं विधिवत रूप से रिश्ता खत्म कर रही हूं।

मानसिक रूप से परेशान होकर मैं इस्तीफा दे दिया है। इसके लिए मैंने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जीतुभाई वाघाणी को पत्र लिखा है। भाजपा कार्यकर्ताओं के पास सिर्फ मार्केटिंग कराते है। हार्दिक पटेल को मेरा समर्थन है। उपलेटा को मैंने अपना चुनावी सेंटर बनाया है। मैं पोरबंदर लोकसभा और माणावदर से विधानसभा की उप चुनाव लड़ूंगी।

सेशन्स कोर्ट के आदेश को गुजरात हाईकोर्ट ने रद्द किया

अहमदाबाद। तालाला के कांग्रेस पूर्व विधायक भगवान बारड को वर्ष १९९५ में २.५३ करोड़ रुपये की खनिज चोरी के केस में दो वर्ष और नौ महीने की सजा सुनाई गई थी। यह फैसले से नाराज हुए भगवान बारड ने वेरावल सेशन्स कोर्ट में अपील करने पर सेशन्स कोर्ट ने ज्युडीशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट के सजा के आदेश खिलाफ स्टे जारी कर दिया था। जिसकी वजह से राज्य सरकार की तरफ से गुजरात हाईकोर्ट में स्पेशियल क्रिमीनल एप्लीकेशन दाखिल करके सजा पर स्टे लगाने पर सेशन्स कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। जिसकी सुनवाई में शुक्रवार को जस्टिस सोनियाबहन गोकानी ने राज्य सरकार की अर्जी मंज ूर करके बारड की सजा पर स्टे लगाने पर वेरावल सेशन्स कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया। इतना ही नहीं हाईकोर्ट ने पूरे मामले की फिर से सुनवाई करने के लिए सेशन्स कोर्ट को आदेश दिया गया। हाईकोर्ट के इस आदेश की वजह से कांग्रेस पूर्व विधायक भगवान बारड की परेशानी बढ़ गई है। तालाला के पूर्व विधायक भगवान बारड ने विधायक पद से सस्पेन्ड करने के लिए और तालाला की उप चुनाव घोषित करने के निर्णय को गुजरात हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। दूसरी तरफ राज्य सरकार ने भी बारड की सजा पर स्टे लगाने पर वेरावल सेशन्स कोर्ट के आदेश के खिलाफ गुज रात हाईकोर्ट में विशेष आपराधिक अर्जी दाखिल की थी। जिसमें वकील जनरल कमलभाई बी. त्रिवेदी और एडिशनल एडवोकेट जनरल प्रकाशभाई के. जानी ने महत्व की दलीलें देते हुए कहा कि, इस केस में सूत्रापाडा की ज्युडीशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सबूतों और कानूनी प्रावधानों को ध्यान में लेकर पूर्व विधायक भगवान बारड को दो वर्ष और नौ महीने की सजा का फैसला सुनाया गया है। इतना ही नहीं ज्युडीशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट ने अपने फैसले में २.५३ करोड़ रुपये की खनिज चोरी होने का स्पष्ट निष्कर्ष दिया है।

स्वामी, मुद्रक व प्रकाशक सुरेश मौर्या द्वारा अष्ट विनायक ऑफसेट एफपी. 149, प्लोट 26 खोडियार नगर, सिद्धीविनायक मंदिर के पास, (भाटेना) हॉ.सो. अंजना सूरत, गुजरात से मुद्रित, एवं 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात से प्रकाशित, संपादक :- सुरेश मौर्या फोन नं. (9879141480) RNI.No. : GUJHIN/2018/75100, E-mail: krantisamay@gmail.com (subject to surat jurisdiction)